[2014] 11 एस.सी.आर. 1096

इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और अन्य

बनाम

नीरज शर्मा और अन्य

(सिविल अपील सं. 2143/2007)

सितंबर 19, 2014

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और वी.गोपाला गौड़ा, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 226 – अपीलार्थी विधि संसथान को चंडीगढ़ में 5.75 एकड़ भूमि का मात्र 9001 रूपए प्रति वर्ग गज की दर से आवंटन – आवंटन के विरुद्ध रिट याचिका – उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और एक उप न्यायाधीश शामिल थे, ने दो अलग-अलग लेकिन सहमति वाले आदेशों द्वारा भूमि के आवंटन को रद्द करने वाली रिट याचिका का निस्तारण किया, हालांकि, उप न्यायाधीश कुछ पैराग्राफ पर सहमत नहीं थे – इसके खिलाफ आवेदन – मनोनीत न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि हालाँकि पीठ ने अलग अलग कारण दर्ज किया, लेकिन निष्कर्ष एक ही था – अपील में, अभिनिर्धारित: याचिकाकर्ता ने एक सदभाविक रूप से रिट याचिका दायर की और उसका आवश्यक अधिकार क्षेत्र था – रिट याचिका सार्वजनिक हित में सम्पोश्नीय

थी क्योंकि संसथान के हित में किया गया आवंटन मनमाना, अनुचित और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था - केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन ने प्रक्रिया का पालन किये बिना अपर्याप्त विचार के लिए अपीलार्थी-संस्थान को उसके पक्ष में भूमि आवंटित करके उदारता प्रदान की – आवंटियों को सार्वजनिक संपत्ति की सहायता से धन कमाने और लाभ कमाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है – उप न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जिसे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपने अलग आदेश से सहमती दी थी और तीसरे नामांकित न्यायाधीश के आदेश में कहा गया था की खंड पीठ के आदेशों में कोई मतभेद नहीं है, कानूनी और वैध है - इस प्रकार, इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है – चंडीगढ़ योजना 1996 में लीज होल्ड आधार पर शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों) को भूमि आवंटन नियम आदि – खंड 18.

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1.1. भूमि आवंटन की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किये बिना ही अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में भूमि का आवंटन कुछ ही दिनों में कर दिया गया। अपीलकर्ताओं का इरादा कानून संस्थान स्थापित करने का था, हालांकि, उनका निजी हित सार्वजनिक हित के खिलाफ था। सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान से आसानी से बचा जा

सकता था यदि भूमि का निपटान सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करके किया जाता। [पैरा 23] [1106-बी, सी]

1.2. प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने एक सदभाविक रिट याचिका दायर की है और उसके पास आवश्यक अधिकार हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में एक स्पष्ट पक्ष दिखाया है जो एक लाभ कमाने वाली कंपनी है। इसलिए यह मानने का एक मजबूत कारण है कि रिट याचिका सार्वजनिक हित में सुनवाई योग्य है। उच्च न्यायालय ने सही निर्धारित किया कि रिट याचिका एक जनहित याचिका है न कि निजी हित याचिका। [पैरा 25] [1110-सी-ई]

1.3. अपीलार्थी रिट याचिका दायर करने में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे को दिखाने में बुरी तरह विफल रहे हैं और वह एक सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति है। चंडीगढ़ प्रशासन को प्रस्तुत ए.ए.ओ.(लेखा परीक्षा) का अभिलेख उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करता है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन ने प्रक्रिया का पालन किये बिना अपर्याप्त विचार के लिए अपने पक्ष में भूमि आवंटित करके अपीलार्थी-संस्थान को अनुदान प्रदान किया। इसलिए, प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य है क्योंकि प्रथम अपीलार्थी के पक्ष में किया गया भूमि का आवंटन मनमाना, अवैध था और यह संविधान के अनुच्छेद 14

का उल्लंघन था। [पैरा 26] [1110 एफ-एच; 1111-ए, बी] [2014] 11 एससीआर

फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन कामगर यूनियन (रजिस्टर्ड) सिंदरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1981(2) एससीआर 52: एआईआर 1981 एससी 344 (1981) 1 एससीसी 568; एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य 1982 एससीआर 365: (1981) पूरक एससीसी 87; दत्तराज नाथूजी थावारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2004 (6) पूरक एससीआर 900: (2005) 1 एससीसी 590 संदर्भित।

2.1. सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान के निर्माण के उद्देश्य से भूमि आवंटित करने के लिए आवश्यक विनियमों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को दी गई विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के पीछे धर्मार्थ इरादे या परोपकारी लक्ष्य के तर्क को ख़ारिज कर दिया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना किसी भी सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं करती है और आवंटी को सार्वजनिक संपत्ति की सहायता से पैसा बनाने या मुनाफाखोरी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 29,32] [1116-बी, जी]

2.2. विवादित आदेशों में उच्च न्यायालय का तर्क कि जांच समिति ने किसी भी वस्तुनिष्ठ मानदंड और नीति का पालन किए बिना आवंटनकर्ता

के पक्ष में संस्थागत साइटें आवंटित की, से सहमत हैं। उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपनाई गई नीति जिसमें भूमि अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में किया गया भूमि का आवंटन बिना कोई सार्वजनिक सूचना दिए और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित पारदर्शी नीति के आभाव में और यहाँ तक कि इस तथ्य की जांच किए बिना किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पहले से ही अत्यधिक जनसँख्या के दबाव में है और यहां तक कि स्कूल स्थलों के आवंटन के मामले में भी चंडीगढ़ योजना 1996 में लीज होल्ड आधार पर शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों) के लिए भूमि का आवंटन नियम आदि के खंड 18 को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे प्रावधान केवल कानून की पुस्तक तक ही सीमित रह गया, यह मनमाना, अनुचित और अन्यायपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। [पैरा 33] [1117-बी-ई]

2.3. यह नहीं कहा जा सकता कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश ने एक अलग राय प्रस्तुत की है ताकि उच्च न्यायालय नियमों और आदेशों के अध्याय 4 के नियम 31 के पैरा 4 के सपठित लैटर पेटेंट के खंड 26 की प्रयोज्यता को आकर्षित किया जा सके। उच्च न्यायालय के आदेशों में निहित निर्देशों के अवलोकन से एक सामान्य प्रभाव का पता चलता है, अर्थात् अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में किया गया संस्थागत भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया गया है क्योंकि यह संविधान के

अनुच्छेद 14 में निहित संवैधानिक दर्शन के अनुरूप नहीं था। नामित न्यायाधीश ने इसे सही रूप से स्वीकार करते हुए कहा है स्पस्ट रूप से विचार प्रक्रिया और दोनों न्यायाधीशों द्वारा इस्तेमाल की गई अभिव्यक्तियों की सापेक्ष कठोरता में अंतर प्रतीत हो सकता है, फिर भी, दोनों न्यायाधीशों ने अभी तक यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि उनके अलग-अलग विचारों में दर्ज दिशाओं में कोई विचलन था। [पैरा 34,35] [1117-जी, एच; 1118-ए-डी]

2.4. उप न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जिसकी सहमति तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपने अलग आदेश से दी थी और तीसरे नामांकित न्यायाधीश के आदेश में यह कहा गया था कि खंड पीठ के आदेशों में कोई मतभेद नहीं है, कानूनी और वैध हैं और ऐसा करते हैं। इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 36,37,38] [1118-ई-जी]

भारत संघ और अन्य बनाम जैन सभा, नई दिल्ली और अन्य 1996 (9) पूरक एससीआर 1: (1997) 1 एससीसी 164; न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल और अन्य बनाम हुडा और अन्य 1996 (3) पूरक एससीआर 597: (1996) 5 एससीसी 510; अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम एम.पी. राज्य और अन्य, 2011 (5) एससीआर 77: (2011) 5 एससीसी 29;

मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ और अन्य 2004 (1) पूरक एससीआर 668: (2004) 5 एससीसी 583-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

1981 (2) एससीआर 52	उल्लेख किया गया है	पैरा 23
1982 एससीआर 365	उल्लेख किया गया है	पैरा 23
2004 (6) पूरक एससीआर 900	उल्लेख किया गया है	पैरा 23
1996 (9) पूरक एससीआर 1	उल्लेख किया गया है	पैरा 27
1996 (3) पूरक एससीआर 597	उल्लेख किया गया है	पैरा 28
2011 (5) एससीआर 77	उल्लेख किया गया है	पैरा 29
2004 (1) पूरक एससीआर 668	उल्लेख किया गया है	पैरा 32

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2143/2007

पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के द्वारा सी.डब्ल्यू पी. सं. 6916/2004 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2005 और सीएम सं. 5016/2005 और सीएम सं.6173/2005 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2006 के निर्णय और आदेश से।

निधेश गुप्ता, तरुण गुप्ता, मोहन के. घोष, अशोक माथुर, ई.सी. अग्रवाल, अपीलार्थियों की ओर से।

जतिंदर कुमार भाटिया, संजय जैन, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया –

वी. गोपाल गौड़ा, न्यायाधिपति

1. यह अपील चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दोनों सदस्यों द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 6916/2004 में पारित आदेश दिनांक 14.2.2005 और सिविल विविध सं. 5016/2005 और सिविल विविध सं. 6173/2005 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2006 के दो अलग-अलग आक्षेपित आदेशों के विरुद्ध निर्देशित है। मामले के संक्षिप्त तथ्य यहां दिए गए हैं: -

2. अपीलार्थी-विधि संस्थान को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सेक्टर 38-ए में 28,373.23 वर्ग गज (5.75 एकड़) भूमि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा 900/- रूपए प्रति वर्ग गज की दर से आवंटित की गई थी। यह दर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पंजाब विकास विनियमन अधिनियम, 1952 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 31/1/100-यूटीएफआई (4-2002/1823) दिनांक 7.3.2002 के तहत केंद्र शासित प्रदेश काह्न्दिगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों को आवंटन के लिए भूमि की दरें तय करते हुए तय की गई थी। भूमि का आवंटन अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड के आधार पर इस शर्त के साथ किया गया था कि प्रारंभिक लीज अवधि 33 वर्ष होगी और दो समान अवधि के लिए

नवीकरणीय होगी, यदि पट्टेदार आवंटन की सभी शर्तों को पूरा करना जारी रखता है।

3. प्रतिवादी नंबर 1, नीरज शर्मा ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 6916/2004 दायर की, जिसमें इस मामले में शामिल भूमि आवंटन की वैधता और वैधता पर सवाल उठाते हुए विभिन्न आधारों का आग्रह किया गया।

4. 14.2.2005 को, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और एक उप न्यायाधीश शामिल थे, ने दो अलग-अलग लेकिन सहमति वाले आदेशों द्वारा भूमि के आवंटन को रद्द करने और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने वाली रिट याचिका का निपटारा किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के संवैधानिक दर्शन के अनुरूप इस मामले में सुधारात्मक कदम उठाए गए और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पात्र व्यक्तियों के पक्ष में शैक्षिक संस्थागत स्थलों के आवंटन के लिए नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवंटन सही हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बनाया गया। हालाँकि, अलग-अलग सहमति आदेश देने के बाद, न्यायाधीश ने निर्णय के बाद की स्क्रिप्ट पर निर्दिष्ट किया कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के कुछ पैराग्राफ संख्या 10,12,13,14 और 15 पर कोई सहमति नहीं थी।

5. आदेशों से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने पत्र पेटेंट के खंड 26 के साथ पढ़े गए उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय 4 (एफ) के नियम 31 के तहत सिविल विविध संख्या 5016/2005 और सिविल विविध संख्या 6173/2005 के तहत आवेदन दायर किए। उन्होंने आग्रह किया कि मतभेद के बिंदुओं पर फैसले के लिए मामले को किसी अन्य पीठ या पूर्ण पीठ के पास भेजा जाए।

6. उच्च न्यायालय के विद्वान नामित न्यायाधीश ने सिविल विविध आवेदन संख्या 5016/2005 और सिविल विविध आवेदन संख्या 6173/2005 को दिनांक 26.4.2006 के आदेश के तहत यह कहते हुए निस्तारण किया कि रिट याचिका की विचारणीयता और रिट याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर खंड पीठ के न्यायाधीशों के बीच मतभेद का कोई मतलब नहीं था। यह उनके द्वारा माना गया था कि हालांकि खंड पीठ के सदस्यों द्वारा अलग-अलग कारण दर्ज किया गए हैं, लेकिन रिट याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर उनके द्वारा दर्ज निष्कर्ष एक की था। आगे यह निर्धारित किया गया कि दोनों आदेश एक सामान्य उद्देश्य को प्रकट करते हैं अर्थात अपीलकर्ता-संस्थान के पक्ष में किये गए भूमि के आवंटन को रद्द करना। विद्वान न्यायाधीश ने आगे स्पष्ट किया है कि आवश्यक निहितार्थ से नीलामी की प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सभी पात्र संभावित आवंटियों को निमंत्रण की आवश्यकता होती है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक दर्शन के अनुरूप होगा।

उपरोक्त शर्तों में स्पष्ट करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने दोनों आवेदन खारिज कर दिए।

7. अपीलार्थी-संस्थान द्वारा दायर इस अपील में खंडपीठ द्वारा दिए गए दिनांक 14.02.2005 के दोनों अलग अलग आदेशों और 2005 की सिविल विविध संख्या ५०१६ और ६१७३ की सुनवाई करने वाले विद्वान नामित न्यायाधीश के आदेश दिनांक 26.4.2006 की सत्यता को कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए चुनौती दी गई।

8. अपीलकर्ता-संस्थान के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निधेश गुप्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि विद्वान नामित न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पारित अलग-अलग आदेशों की सराहना न करके गलती की है, जिन्होंने अलग-अलग आदेश दिए हैं। और अलग-अलग आदेश, जो प्रकृति में बिल्कुल विरोधाभासी हैं और उनमें कोई समानता नहीं है। विद्वान न्यायाधीश यह समझने में असफल रहे कि 'निर्णय के बाद की स्क्रिप्ट' में भी, विद्वान न्यायाधीशों में से एक ने दो विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेदों को स्पष्ट रूप से बताया है और केवल इस आधार पर मामले को एक वृहद पीठ को भेजा जाना चाहिए था।

9. आगे यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि इस अपील में शामिल भूमि उचित जांच के बाद और भूमि के विशिष्ट उपयोग की शर्त के साथ भूमि की प्रकाशित और

अधिसूचित दरों पर अपीलकर्ता-संस्थान को आवंटित की गई थी। लीज होल्ड आधार और अपीलकर्ता-संस्थान के पक्ष में भूमि के आवंटन से कोई भी नगर नियोजन प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि प्रश्न में भूमि का क्षेत्र संस्थागत क्षेत्र में स्थित है जहां शैक्षणिक संस्थान कार्य कर रहे हैं।

10. आगे यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज न करके गंभीर गलती की है, जिसने व्यक्तिगत हित के लिए रिट याचिका दायर की थी क्योंकि उसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा आवासीय स्थल आवंटित नहीं किया गया था।

11. उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने में और गलती की है कि अपीलार्थी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए, भूमि उन्हें आवंटित की गई थी, हालांकि आक्षेपित निर्णयों में कोई भी आधार नहीं दिखाया गया है।

12. उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार नहीं करने में गलती की है कि अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में भूमि का आवंटन पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा अपनाई जाने वाली और पालन की जाने वाली नियमित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था और इसमें, अपीलकर्ता-संस्थान, जो गैर लाभकारी संस्थान भी है, के पक्ष में भूमि आवंटित करने में उक्त प्रक्रिया किसी भी तरह का कोई विचलन नहीं था।

13. यह भी तर्क दिया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भूमि की नीलामी नहीं की गई है बल्कि इसे शहर और समाज की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर योग्य व्यक्ति/संस्थान को आवंटित किया गया है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के उद्देश्यों के लिए भूमि के आवंटन में हस्तांतरण के साथ साथ उपयोग पर भी प्रतिबन्ध है और इसलिए, यह सामान्य भूमि दरों (अर्थात वाणिज्यिक और आवासीय) से भिन्न है, जिसमें ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं हैं और स्वतंत्र रूप से विपणन योग्य हैं।

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि को कुछ शर्तों के साथ आवंटित किया गया था, (ए) शुरू में 33 वर्षों के लिए लीज होल्ड के आधार पर (बी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गैर हस्तांतरणीय और (ग) उपयोग केवल विधि संस्थान के लिए था। अपीलार्थी-संस्थान ने पट्टे की राशि का 25 प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के पास जमा कर दिया, जहाँ अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में विचाराधीन भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 22.01.2004 को आवंटन पत्र पर जारी किया गया।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर एक जनहित याचिका के रूप में डब की गई रिट याचिका तुच्छ, दुर्भावनापूर्ण और अवैध है, क्योंकि यह सूचना के स्रोत का खुलासा नहीं करती है।

16. दूसरी ओर, प्रथम प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता है जो भूमि के कानूनों के प्रति गहरी चिंता रखता है।

17. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता भूमि का आवंटन प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की नीति, सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनों के विपरीत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे में है।

18. प्रतिवादियों ने आगे तर्क दिया है कि उक्त आवंटित भूमि का बाज़ार मूल्य 50/- करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन अपीलार्थी-संस्थान को केवल 2.5 करोड़ रुपये की राशी के लिए लीज के माध्यम से प्रदान किया गया था, जो कानून में अनुमत नहीं है और इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।

19. आगे तर्क दिया गया है कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पक्ष में भूमि आवंटन के नियमों के अनुसार, बिना विज्ञापन और पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए किसी भी संस्थान को कोई भी भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है।

20. दोनों पक्षों की ओर से आग्रह किये गए उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्कों के आधार पर निम्नलिखित बिंदु हमारे विचार के लिए आएंगे:

(i) क्या जनहित में दायर रिट याचिका है सम्पोश्नीय है या नहीं और क्या रिट याचिकाकर्ता के पास है रिट याचिका दायर करने का अधिकार है?

(ii) क्या उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित अलग लेकिन सहमति वाले आदेश, जिन पर नामांकित तीसरे न्यायाधीश ने सहमति व्यक्त की थी, कानूनी और वैध हैं या क्या इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

(iii) क्या अपीलकर्ता-संस्थान के पक्ष में किया गया भूमि आवंटन आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ "चंडीगढ़ योजना 1996 में लीज होल्ड के आधार पर शैक्षिक संस्थानों (स्कूलों) के लिए भूमि आवंटन नियमों आदि" की प्रयोज्यता का उल्लंघन है?

(iv) क्या आदेश?

बिन्दु संख्या 1 का उत्तर

21. हम सबसे पहले रिट याचिका की पोषणीयता और रिट याचिकाकर्ता, प्रतिवादी नंबर 1, जिसने रिट याचिका दायर की है, के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार और उत्तर देंगे।

22. विचाराधीन संपत्ति केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन की है। हमारे संविधान के तहत दर्शन, यह एक सार्वजनिक संपत्ति है और इसलिए, लोगों से संबंधित है। इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन उस भूमि का न्यासी है जिसका कर्तव्य यह देखना है कि संपत्ति का आवंटन चंडीगढ़

प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके पात्र व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है, और इसे बर्बाद होने की अनुमति या इसे औने पाने दाम पर बेचान नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि मौजूदा मामले में किया गया है, जैसा कि इसके लेखा परीक्षा विभाग ने ही बताया है कि सरकारी खजाने को लगभग 139 करोड़ रुपये का स्पष्ट नुकसान हुआ।

23. यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में विचाराधीन भूमि का निस्तारण भूमि आवंटन के लिए अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ दिनों के भीतर किया गया था। हमें कानून संस्थान स्थापित करने के अपीलकर्ताओं के इरादे पर संदेह नहीं है, हालांकि, उनका निजी हित सार्वजनिक हित के खिलाफ है। सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान से आसानी से बचा जा सकता था यदि पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से संबंधित भूमि का निस्तारण किया जाता।

24. इसके अलावा, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, याचिकाकर्ता पंजाब राज्य का निवासी है और आयकर दाता भी है। अपीलार्थियों द्वारा यह न तो दिखाया गया है और न ही साबित किया गया है कि वह एक (i) हस्तक्षेप करने वाला हस्तक्षेपकर्ता, (ii) कि वह दुर्भावनापूर्ण इरादे के तहत कार्य कर रहा है या (iii) कि उसे चंडीगढ़ प्रशासन या अवन्ती के साथ अपने व्यक्तिगत मतभेदों को निपटाने के लिए

किसी ने खड़ा किया है। रिट याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निस्तारण करने के लिए हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना चाहेंगे कि पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए एक जनहित याचिका है फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन कामगर यूनियन (रजिस्टर्ड) सिंदरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [(1)], में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

> " 29-30 . ..... न्यायिक उपचार के लोकतंत्र के संदर्भ में, लोकपाल के अभाव में नागरिक कहां खड़ा है? सरकारी खजाने के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रशासनिक शक्ति के (दुर्लभ, फिर भी वास्तविक) दुरुपयोग के सामने, विशेष रूप से जहां विकासात्मक विस्तार में आवश्यक रूप से भारी व्यय और सहवर्ती भ्रष्टाचार शामिल है, क्या सार्वजनिक निकाय पोस्टमार्टम के अलावा चुनौती से प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं? संसदीय अंग. कानूनी नियंत्रण और निगमित स्वायत्तता की गतिशीलता के आलोक में पढ़ें, न्यायिक प्रक्रिया की क्या भूमिका है?
>
> XXX XXX
>
> XXX

47 ..... फिर भी, प्रशासन में निष्पक्षता, कार्रवाई में प्रामाणिकता और सार्वजनिक व्यवसाय के उचित प्रबंधन के बुनियादी नियमों का उल्लंघन होने पर, न्यायसंगत हो जाएंगे।

48. यदि कोई नागरिक इस देश के 660 मिलियन लोगों में से किसी एक के स्वामित्व से परे किसी भी हित या चिंता के बिना एक पथिक या अधिकारिक हस्तक्षेपकर्ता से अधिक कुछ नहीं है, तो न्यायालय का दरवाजा उसके लिए खुला नहीं होगा। लेकिन, यदि वह किसी ऐसे संगठन से संबंधित है, जिसकी विषय-वस्तु में विशेष रुचि है, यदि उसकी किसी व्यस्त व्यक्ति से अधिक गहरी चिंता है, तो उसे गेट पर नहीं बताया जा सकता है, हालांकि उसके द्वारा उठाया गया मुद्दा न्यायसंगत है या नहीं, यह अभी भी हो सकता है। विचार किया जाना बाकी है. इसलिए, मेरा विचार है कि वर्तमान याचिका स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 226 के तहत स्वीकार्य होगी।" (जोर दिया गया)

इसी तरह, एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य [(2)] के मामले में, इस न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के संबंध में स्पष्ट रूप से कानून निर्धारित किया है, जो निम्नानुसार हैः

"18 ..... जब भी राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के किसी कार्य या चूक के कारण कोई सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक चोट होती है जो संविधान या कानून के विपरीत है, तो जनता का कोई भी सदस्य सदभाविक रूप से कार्य करता है और पर्याप्त हित रखता है, तो ऐसी सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए कार्रवाई कर सकता है। खड़े होने का सख्त नियम जो इस बात पर जोर देता है कि केवल वही व्यक्ति जिसे एक विशिष्ट कानूनी चोट लगी है, न्यायिक निवारण के लिए कार्रवाई कर सकता है, उसे शिथिल कर दिया गया है और एक व्यापक नियम विकसित किया गया है जो जनता के किसी भी सदस्य को खड़ा करता है जो केवल एक व्यस्त निकाय नहीं है या एक हस्तक्षेपकारी हस्तक्षेपकर्ता लेकिन जिसकी कार्यवाही में पर्याप्त रूचि है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी नागरिक द्वारा राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जोखिम राज्य या ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिक जिम्मेदारी और देखभाल के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा जिससे न्याय प्रशासन में सुधार होगा..... यह भी इंगित करना आवश्यक है कि यदि कोई भी सार्वजनिक गलत या

सार्वजनिक चोट के संबंध में न्यायिक निवारण के लिए कार्रवाई करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, तो न केवल वैधता का कारण प्रभावित होगा, बल्कि लोगों के पास ऐसे निवारण के लिए कोई न्यायिक उपचार नहीं होगा। सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक क्षति सड़क पर आ सकती है और उस प्रक्रिया में, कानून का शासन गंभीर रूप से बाधित हो जाएगा.....।

19. एक अन्य कारण यह भी है कि क्यों अधिकार क्षेत्र के नियम को उदार बनाने की आवश्यकता है। आज हम पाते हैं कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संगठित सामाजिक कार्रवाई के एक उपकरण के रूप में कानून का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के जिस कार्य पर हम लगे हुए हैं, उससे विकासात्मक गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है और कानून का उपयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यह लोगों के एक बड़े वर्ग के पक्ष में अधिकारों की एक नई श्रेणी बना रहा है और आम आदमी तक सामाजिक न्याय पहुंचाने की दृष्टि से राज्य और सार्वजनिक अधिकारियों पर कर्तव्यों की एक नई श्रेणी थोप रहा है... । दूसरे शब्दों में, कर्तव्य वह है जो

व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित नहीं है। अब यदि ऐसे सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन को बिना निवारण के छोड़ दिया जाता है क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसे कोई विशिष्ट कानूनी चोट लगी हो या जो ऐसे सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित निर्णय से संबंधित कार्यवाही में भाग लेने का हकदार हो, तो ऐसे सार्वजनिक कर्तव्य को निभाने में विफलता अनियंत्रित हो जाएगा और यह कानून के शासन के प्रति अनादर को बढ़ावा देगा। यह भ्रष्टाचार और अकुशलता के लिए भी द्वार खोलेगा क्योंकि सार्वजनिक शक्ति के प्रयोग पर कोई रोक नहीं होगी, सिवाय इसके कि राजनीतिक तंत्र द्वारा क्या प्रदान किया जा सकता है, जो सर्वोत्तम स्थिति में केवल सीमित नियंत्रण का प्रयोग करने में सक्षम होगा और सबसे बुरी स्थिति सत्ता का दुरुपयोग या गलत उपयोग में भागीदार बन सकता है। यह समुदाय के वंचित वर्गों के लाभ के लिए बनाए गए नए सामाजिक सामूहिक अधिकारों और हितों को भी अर्थहीन और अप्रभावी बना देगा।

20. ..... यदि सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू किया जाना है और सामाजिक सामूहिक "विस्तारित" अधिकारों और हितों की रक्षा करनी है, तो हमें सार्वजनिक विचारधारा वाले

व्यक्तियों और संगठनों की पहल और उत्साह का उपयोग करके उन्हें न्यायालय ने जाने और सामान्य या सामूहिक हित के लिए कार्य करने की अनुमति देनी होगी, भले ही वे अपने अधिकारों में सीठे तौर पर घायल न हों। यही कारण है कि जनहित याचिका में - सार्वजनिक चोट के निवारण, सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने, सामाजिक, सामूहिक, "विस्तारित" अधिकारों और हितों की रक्षा करने या सार्वजनिक हित की पुष्टि करने के उद्देश्य से की गई याचिका में, कोई भी नागरिक जो ईमानदारी से कार्य कर रहा है और जो पर्याप्त रुचि होने पर उसे दर्जा दिया जाना चाहिए। जनता के किसी सदस्य को प्रतिष्ठा देने के लिए पर्याप्त हित क्या है, यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। अदालत के लिए "पर्याप्त हित" को परिभाषित या सीमित करने के उद्देश्य से कोई कठोर नियम या कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला निर्धारित करना संभव नहीं है। इसे आवश्यक रूप से न्यायालय के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए.....।

XXX XXX

XXX

23. इसलिए हम यह मानेंगे कि पर्याप्त हित रखने वाला जनता का कोई भी सदस्य सार्वजनिक कर्त्तव्य के उल्लंघन या संविधान या कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक चोट के लिए न्यायिक निवारण के लिए कार्यवाही कर सकता है और ऐसे सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने और ऐसे संवैधानिक या कानूनी प्रावधान का पालन करने की मांग कर सकता है .....।"

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, दत्तराज नाथूजी थवारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [(3)] के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जनहित याचिका एक हथियार है जिसका उपयोग बहुत सावधानी और सतर्कता से किया जाना चाहिए। इसे नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कानून के शस्त्रागार में एक प्रभावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जनहित याचिका का उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक चोट का निवारण करना होना चाहिए।

25. यह हमारे लिए स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता ने एक सदभाविक रिट याचिका दायर की है और उसके पास आवश्यक अधिकार हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में

एक स्पष्ट पक्षपात दिखाया गया है जो एक लाभ कमाने वाली कंपनी है और जिसने इस न्यायालय को यह नहीं दिखाया है कि उसके पक्ष में भूमि का आवंटन कानून के अनुसार है। इसलिए, हमारा विचार है कि यह मानने का एक मजबूत कारण है कि रिट याचिका जनहित में बनाए रखने योग्य है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हैं, जिसमें उसने सही निर्णय दिया है कि रिट याचिका एक सार्वजनिक याचिका है, न कि एक निजी हित याचिका। विचाराधीन रिट याचिका प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर की गई पहली याचिका है और उत्प्रेषण रिट जरी करके सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए संवैधानिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का उसका पहला प्रयास है।

26. अपीलार्थी यह दिखाने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि रिट याचिका दायर करने में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादा था और हम अपने आदेश में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के द्रष्टिकोण से सहमत हैं, जिन्होंने यह निर्धारित किया है कि वह एक जन-उत्साही व्यक्ति हैं। उनके द्वारा बताया गया कारण निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। और चंडीगढ़ प्रशासन को प्रस्तुत ए.ए.ओ. (लेखा परीक्षा) का रिकॉर्ड उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करता है। इसके अलावा यह देखा गया है कि महामहिम, पंजाब के राज्यपाल-सह-प्रशासक, चंडीगढ़ ने अपने निर्णय में सही निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष भूमि के विवादित आवंटन में सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रक्रिया का पालन किये बिना अपर्याप्त विचार के लिए अपीलार्थी-संस्थान के अपने पक्ष में भूमि आवंटित करके उसे अनुदान प्रदान की है। इसलिए, हम मानते हैं कि पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका भूमि के आवंटन के रूप में बनाए रखने योग्य है। क्योंकि प्रथम अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में किया गया भूमि का आवंटन मनमाना, अवैध है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

<u>बिंदु संख्या 2, 3 और 4 का जवाब</u>

27. हमने अपीलकर्ता-संस्थान के पक्ष में किए गए भूमि आवंटन आदेश की वैधता के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार और परीक्षण किया है। पहले प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि सार्वजनिक हित की सेवा के लिए घोषित उद्देश्य के साथ निजी शैक्षणिक संस्थानों को सार्वजनिक भूमि का कौड़ी के दाम पर या बिना किसी कीमत पर आवंटन "धर्मार्थ शिक्षा" जो साक्षरता का पवित्र कारण है, के सिद्धांत के विपरीत है। उपरोक्त कानूनी मुद्दे की इस न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम जैन सभा, न्यू दिल्ली और अन्य [(4)] के मामले में कल्पना की थी जिसमे निजी शिक्षण संस्थान की स्थापना के पीछे धर्मार्थ इरादों या परोपकारी लक्ष्य के पीछे की दलील को इस न्यायालय ने यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया की :

"11 ..... हम यह मानना उचित समझते हैं कि अब समय आ गया है कि सरकार स्कूलों और अन्य धर्मार्थ संस्थानों को भूमि आवंटन से संबंधित संपूर्ण नीति की समीक्षा करे। जहां सार्वजनिक संपत्ति ऐसे संस्थानों को व्यावहारिक रूप से मुफ्त में दी जा रही है, वहां भूमि के उपयोगकर्ता और उस पर स्थापित स्कूलों या अन्य संस्थानों के कार्य करने के तरीके के संबंध में कड़ी शर्तें लगानी होंगी। लगाई गई शर्तें सार्वजनिक हित के अनुरूप होनी चाहिए और हमेशा यह निर्धारित होना चाहिए कि उनमें से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, भूमि सरकार द्वारा फिर से हासिल कर ली जाएगी। न केवल ऐसी शर्तें निर्धारित की जानी चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी भी की जानी चाहिए कि उन शर्तों का व्यवहार में पालन किया जा रहा है या नहीं। हालाँकि हम प्रतिवादी द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्कूल के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह सामान्य ज्ञान है कि कुछ स्कूल पूरी तरह से व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे हैं। चंदे और फीस के तौर पर भारी मात्रा में शुल्क वसूला जा रहा है. सवाल यह है कि क्या ऐसे संस्थानों को कम कीमत पर भूमि आवंटित करने का कोई औचित्य है? व्यावहारिक रूप से बिना किसी

कीमत पर लोगों की भूमि का आवंटन सार्वजनिक हित की सेवा के लिए है, यानी शिक्षा का प्रसार या अन्य धर्मार्थ उद्देश्य; इसका उद्देश्य आवंटियों को सार्वजनिक संपत्ति की सहायता से पैसा कमाने या मुनाफाखोरी करने में सक्षम बनाना नहीं है। हमें विश्वास है कि सरकार इसमें शामिल टिप्पणियों के आलोक में इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी।"

28. इसके अलावा, एक अन्य मामले में, इस न्यायालय ने आवंटन समिति द्वारा किए गए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया, भले ही अधिकांश आवंटियों ने भवनों का निर्माण किया था, क्योंकि, आवंटन समिति ने एक खुले विज्ञापन के माध्यम से भूमि के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए किसी तर्कसंगत या उचित मानदंड का पालन नहीं किया था। न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल और अन्य बनाम हुडा और अन्य [(5)] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया, जो इस प्रकार हैः

"4 ..... इसलिए, सार्वजनिक प्राधिकारियों को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक विशिष्ट विनियम या वैध दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता होती है; अन्यथा, हितकारी प्रक्रिया सार्वजनिक नीलामी द्वारा होगी। इसलिए, खंड पीठ ने उचित रूप से इंगित

किया है कि ऐसे वैधानिक विनियम के आभाव में निजी संस्थानों या व्यक्तियों को स्थल आवंटित करने की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कानून में सही नहीं था।"

29. इसके अलावा, हमें अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस बनाम एम.पी. राज्य और अन्य [(6)] के मामले का उल्लेख करना होगा, जिसमें यह इस न्यायालय ने सार्वजनिक संपत्ति के आवंटन के संबंध में इस न्यायालय के मामलों की श्रृंखला पर विचार करने के बाद संक्षेप में कानून निर्धारित किया है:

"50. प्रस्तावना में निर्धारित न्याय और समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, राज्य और उसकी एजेंसियों/यंत्रियों को विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक संस्थाओं और अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करना होगा। संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून उन्हें समतावादी समाज के निर्माण के लिए बनाए गए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की शक्तियां प्रदान करते हैं। लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ और लाभ प्रदान करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं और अधिकारियों/पदाधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग में हमेशा विवेक का एक तत्व होता है, जिसका उपयोग व्यापक सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना आवश्यक है... हमारे संवैधानिक ढांचे में, राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के किसी भी पदाधिकारी के पास पूर्ण या निरंकुश

विवेकाधिकार नहीं है। निरंकुश विवेक का विचार ही संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के साथ पूरी तरह से असंगत है और कानून के शासन की अवधारणा के विपरीत है।

XXX XXX XXX

54. ब्रीन बनाम अमालगामेटेड इंग. यूनियन में, लॉर्ड डेनिंग एमआर ने कहाः (क्यू.बी पी. 190, बी-सी)

> "..... एक सांविधिक निकाय का विवेकाधिकार कभी भी निरंकुश नहीं होता है। यह एक विवेकाधिकार है जिसका उपयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। इसका मतलब कम से कम यह हैः वैधानिक निकाय को प्रासंगिक विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए और अप्रासंगिक से नहीं। अगर वह निर्णय बाहरी विचारों से प्रभावित होता है जो इसे ध्यान में नहीं रखना चाहिए था, तो निर्णय खड़ा नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैधानिक निकाय ने सद्भावना से कार्य किया हो; फिर भी निर्णय रद्द कर दिया जाएगा। यह पैडफील्ड बनाम कृषि मंत्री, मत्स्य पालन और खाद्य द्वारा स्थापित किया गया है, जो आधुनिक प्रशासनिक कानून में एक मील का पत्थर है।"

55. लेकेर एयरवेज लिमिटेड बनाम व्यापर विभाग में लॉर्ड डेनिंग ने युद्ध के समय कानून में विशिष्ट प्रावधानों को खारिज करते हुए नागरिक उड्डयन अधिकारियों को निर्देश देने के मंत्री के विशेषाधिकार पर चर्चा की और कहा: (क्यूबी पृष्ठ 705, एफ-जी)

> 'यह देखते हुए कि विशेषाधिकार जनता की भलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विवेकाधीन शक्ति है, यह इस प्रकार है कि इसके प्रयोग की जांच अदालतों द्वारा की जा सकती है, जैसे कि कोई अन्य विवेकाधीन शक्ति जो कार्यपालिका में निहित है।'

56. इस न्यायालय ने बहुत पहले इस निरंकुश विवेक के सिद्धांत को खारिज कर दिया है। एस.जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ, रामास्वामी, न्यायाधिपति ने इस बात पर जोर दिया कि मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति कानून के शासन द्वारा शासित प्रणाली की नींव है और कहा गया है: (एआईआर पी । 1434, पैरा 14)

> '14. इस संदर्भ में इस बात पर जोर देना जरूरी है कि मनमानी शक्ति का अभाव कानून के शासन की पहली अनिवार्यता है जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था आधारित है। कानून के शासन द्वारा शासित प्रणाली में, विवेकाधिकार, जब कार्यकारी अधिकारियों को दिया जाता

है, तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के भीतर ही सीमित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कानून के शासन का अर्थ है कि निर्णय ज्ञात सिद्धांतों और नियमों को लागू करके किए जाने चाहिए और सामान्य तौर पर, ऐसे निर्णय पूर्वानुमानित होने चाहिए और नागरिक को पता होना चाहिए कि वह कहां है। यदि कोई निर्णय बिना किसी सिद्धांत के या बिना किसी नियम के लिया जाता है तो यह अप्रत्याशित होता है और ऐसा निर्णय कानून के शासन के अनुसार लिए गए निर्णय के विपरीत होता है.....'

XXX XXX XXX

59. कस्तुरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य में, भगवती, न्यायाधिपति ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहाः (एससीसी पीपी 13-14, पैरा 14)

'14. जहां कोई भी सरकारी कार्रवाई ऊपर चर्चा की गई तर्कसंगतता और सार्वजनिक हित के परीक्षण को पूरा करने में विफल रहती है और तर्कसंगतता की गुणवत्ता में कमी या सार्वजनिक हित के तत्व की कमी पाई जाती है, तो इसे अमान्य माना जाएगा.....।'

61. न्यायालय ने पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों की डीलरशिप देने के लिए मंत्री द्वारा पारित आदेशों में दर्ज कारणों का भी उल्लेख किया और कहा: (कॉमन कॉज केस, एससीसी पी.554, पैरा 24)

> '24. ..... जबकि अनुच्छेद 14 प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखते हुए एक उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, यह एक ही श्रेणी में आने वाले कई व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चयन करने की शक्ति को अनुमति नहीं देता है। एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मानदंड/प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए ताकि एक ही वर्ग या श्रेणी से संबंधित सदस्यों के बीच चयन तर्क, निष्पक्ष खेल और गैर-मनमानापन पर आधारित हो। नीतिगत रूप से यह निर्धारित करना आवश्यक है कि एक ही श्रेणी में आने वाले दो व्यक्तियों के बीच प्राथमिकताएँ कैसे आवंटित की जाएंगी.....।'

62. श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम यू.पी. राज्य में, न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों के पूर्ण विवेकाधिकार और न्यायिक समीक्षा से उनकी कार्रवाई की प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर आधारित तर्क को स्पष्ट रूप से ख़ारिज कर दिया और कहाः (एससीसी पीपी 236, 239-40)

"29. इस समय इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सरकारी नीति के मामलों में भी लागू होता है और यदि सरकार की नीति या कोई कार्रवाई, यहाँ तक कि संविदात्मक मामलों में भी, तर्कसंगतता की कसौटी को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो यह असंवैधानिक होगा.....।"

उपर्युक्त मामलों के आलोक में, हमें अपने निष्कर्ष को दर्ज करना होगा कि एक सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान के निर्माण के उद्देश्य से भूमि आवंटित करने के लिए आवश्यक विनियमों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को दी गई विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

30. हम आगे मानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के संदर्भ में एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसलिए, राज्य "शिक्षा के व्यावसायीकरण" को प्रतिबंधित करने की अपनी क्षमता में है।

31. मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ और अन्य [(7)] (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः

"72. जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन का सवाल है, यह बताना पर्याप्त है कि इसका अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन संस्थान निर्विवाद रूप से आवंटन के नियमों और शर्तों से बंधे हैं। यदि आवंटियों द्वारा आवंटन के ऐसे नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो उपयुक्त वैधानिक प्राधिकारी कानून के अनुसार उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।“

32. इसलिए, हम अपीलकर्ता शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के पीछे धर्मार्थ इरादे या परोपकारी लक्ष्य के तर्क को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि इसकी स्थापना किसी भी सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं करती है और हम आवंटियों को सार्वजनिक संपत्ति की सहायता से पैसा कमाने या मुनाफाखोरी करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

33. इसके अलावा, "चंडीगढ़ योजना, 1996 में लीज होल्ड आधार पर शैक्षणिक संस्थानों (स्कूलों) के नियमों आदि को भूमि आवंटन" के खंड 18 के पीछे वैधानिक उद्देश्य के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ में स्थापित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संस्थानों की आवश्यकताओं की पहचान करने का कोई

व्यवस्थित अभ्यास नहीं किया गया है। इस प्रकार हम आक्षेपित आदेशों में उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत हैं कि वरिष्ठ और जिम्मेदार पदाधिकारियों की जांच समिति ने किसी भी वस्तुनिष्ठ मानदंड और नीति का पालन किए बिना आवंटियों के पक्ष में संस्थागत स्थलों का आवंटन किया। जाँच समिति ने प्रथम अपीलकर्ता के पक्ष में भूमि आवंटित करने में ऐसे तरीके से कार्य किया जो इस न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही माना है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपनाई जाने वाली नीति जहाँ भूमि का आबंटन अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था बिना कोई सार्वजनिक सूचना दिए और इसके अभाव में संस्थान वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित एक पारदर्शी नीति यहाँ तक कि इस तथ्य की जांच करते हुए कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पहले से ही अधिक आबादी के अत्यधिक दबाव में है और यहां तक कि योजना, 1996 के खंड 18 को लागू करने का कोई प्रयास नहीं करके स्कूल स्थलों के आवंटन के मामले में भी, इस प्रकार सीमित है केवल कानून पुस्तक के लिए उक्त प्रावधान मनमाना है, अनुचित और अन्यायपूर्ण है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का विरोध करता है।

34. अब हम तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में व्यक्त की गई राय पर आते हैं, जिसे सिविल विविध आवेदनों की सुनवाई करने वाले नामित न्यायाधीश द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, हालांकि खंड

पीठ के सदस्यों द्वारा अपने आदेश में अलग-अलग कारण दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने सीडब्ल्यूपी संख्या 6916/2004 का निस्तारण किया है, उनका निष्कर्ष भी यही था। इसलिए, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को एक अलग राय प्रदान करने वाला नहीं कहा जा सकता है ताकि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय 4, पैरा एफ के नियम 31 सपठित लैटर पेटेंट के खंड 26 की प्रयोज्यता को आकर्षित किया जा सके।

35. उच्च न्यायालय के आदेशों में निहित निर्देशों का अवलोकन एक सामान्य प्रभाव प्रकट करता है, अर्थात अपीलार्थी-संस्थान के पक्ष में किया गया संस्थागत भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया गया है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित संवैधानिक दर्शन के अनुरूप नहीं था। इसे सिविल विविध क्रमांक 5016/2005 और सिविल विविध क्रमांक 6173/2005 की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के विद्वान नामांकित न्यायाधीश ने भी स्वीकार किया था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और सहयोगी न्यायाधीश, जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश काह्न्दिगढ़ के प्रशासन को निर्देश जरी किया हैं, के बीच कोई मतभेद या विचलन नहीं है। नामित न्यायाधीश द्वारा सही बताया गया है कि स्पष्ट रूप से विचार प्रक्रिया और दोनों विद्वान न्यायाधीशों द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों की सापेक्ष कठोरता

में अंतर प्रतीत हो सकता है, फिर भी, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि उनके अलग अलग विचारों में दर्ज दिशा निर्देशों में कोई विचलन था।

36. इस प्रकार हम मानते हैं कि विद्वान उप न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जिसे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपने अलग आदेश द्वारा सहमती व्यक्त की थी और तीसरे नामित न्यायाधीश के आदेश में कहा गया था कि खंड पीठ के आदेश कानूनी और वैध हैं और कोई मतभेद नहीं है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

37. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं के खिलाफ आक्षेपित आदेशों में की गई कुछ टिप्पणियाँ पूरी तरह से अनुचित हैं और उन्हें हटा दिया गया है।

38. पूर्वगामी कारणों को देखते हुए, हमें इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में लागू आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार अपील ख़ारिज की जाती है। स्थगन आदेश दिनांक 16.04.2007 निरस्त हो जायेगा।

अपील खारिज की गई।

निधि जैन

1. एआईआर 1981 एससी 344, (1981) 1 एससीसी 568

2. (1981) पूरक एससीसी 87

3. (2005) 1 एससीसी 590

4. (1997) 1 एससीसी 164

5. (1996) 5 एससीसी 510

6. (2011) 5 एससीसी 29

7. (2004) 5 एससीसी 583

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी

संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****